हिमाचल प्रदेश को विद्युत परियोजनाओं का हस्तान्तरण

2031. **श्री महेश्वर सिंह** : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश के सीमा क्षेत्र के भीतर लगाई गई थी विद्युत परियोजनाओं को हिमाचल प्रदेश सरकार को हस्तांतरित करने के संबंध में केन्द्रीय सरकार को ई प्रस्ताव भेजा है अथवा पत्र व्यवहार ा है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) उन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जिन्हें हिमाचल प्रदेश सरकार अपने अधिकार में लेना चाहती है; और

(घ) केन्द्रीय सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय): (क) से (घ) हिमाचल प्रदेश द्वारा समय-समय पर पंजाब राज्य बिजली बोर्ड के स्वामित्व वा जोगिन्दर नगर (शानन) पावर हाऊस को हिमाचल प्रदेश को हस्तांतरित किए जाने संबंधी मुद्दा उठाया गया है । इस मामले में भारत सरकार का दृष्टिकोण जिसके बारे हिमाचल प्रदेश सरकार को पहले ही सूचित किया जा चुका है, यह है कि चूंकि इस पावर हाऊस का पंजाब को आबंटन, अन्य बातों के साथ-साथ तत्कालीन सिंचाई एवं विद्युत मंत्री और पंजाब, हरियाणा एवं हिमाचल प्रदेश के मुख्य मंत्रियों के बीच अप्रैल, 1967 में नई दिल्ली में हुए विचार-विमर्श के बाद लिए गए निर्णय के आधार पर दिया गया था, अतः इस मामले पर पुनः विचार किया जाना वांछनीय नहीं होगा ।

Pending power Projects of Maharashtra

2052. SHRI VITHALRAO MADHAVRAO JADHAV:
SHRI SURENDER SINGH:

Will the Minister of POWER be pleased to refer to answer to Starred Question 87 given in the Rajya Sabha on the 14th July, 1992 and state:

(a) what is the number of projects from Maharashtra which are yet to be cleared; and

(b) if so, by when they will be clered?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF POWER (SHRI KALP NATH RAI): (a) Eight power generation projects and three transmission projects of Maharashtra are yet to be cleared by the Union Government.

(b) Schemes are accorded techno-economic clearance subject to the fulfilling of certain conditions regarding tieing up of inputs and also completing the formalities required under Section 29 of the Electricity (Supply) Act, 1948. This is being done to enable project authorities to take action for obtaining the requisite linkages and clearances from other Departments, as parallel activities, before obtaining the investment sanctions.

Visit by World Bank Team in India for Negotiation Loan to NTPC

2053. SHRI RAMDAS AGARWAL: Will the Minister of POWER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a high level World Bank team visited India in June, 1992 to negotiate for a World Bank loan to be disbursed to finance NTPC power projects in the country;